न्यू नॉर्मल पर उठते प्रश्न | ऑनलाइन अधिगम

बी.एस. ऋषिकेश

जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी आई है, तब से हमारे शब्द संग्रह में एक नया वाक्यांश जुड़ गया है और वह है – *न्यू नॉर्मल* और इसका प्रयोग कई चीज़ों के लिए किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो यह बड़ी तेज़ी से सुनाई देने लगा है, ख़ासकर स्कूलों के सन्दर्भ में। इस लेख में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या वर्तमान समय के शैक्षिक प्रयास को 'सामान्य' माना जा सकता है और क्या उसे '*न्यू नॉर्मल*' कहा जा सकता है।

न्यू नॉर्मल

आइए बहुत संक्षेप में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में इस *न्यू नॉर्मल* का पता लगाएँ। सरल शब्दों में कहें, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम-आधारित सामग्री का उपयोग करते हैं। जिसे या तो उनके शिक्षकों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाता है *(समकालिक विधा)* या स्कूल ध्यानपूर्वक बनाई गई सामग्री को रिकॉर्ड करके अपने डिजिटल साधन के माध्यम से भेजते हैं *(असमकालिक विधा)*। इन दोनों विधियों में विद्यार्थी विषय-सामग्री के सम्पर्क में तो आते हैं, लेकिन उससे सम्बन्धित सार्थक चर्चा या रचनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता।

हाँ, समकालिक विधा में कुछ शिक्षक विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह सतही स्तर पर रहता है। पिछले कुछ महीनों के अपने व्यक्तिगत अनुभव को देखते हुए मेरा मानना है कि शिक्षक अपनी चर्चाओं में गहराई से जाने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि इस विधा की कई सीमाएँ हैं। जिसने भी *न्यू नॉर्मल* के पिछले कुछ महीनों में पढ़ाया है, वे इस बात से सहमत होंगे कि अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी आधारित तरीक़ों की अपनी सीमाएँ हैं। सामान्य तरीक़े यानी आमने-सामने बैठकर पढ़ाने वाले तरीक़े का अनुकरण सम्भव नहीं है, विशेष रूप से नियमित आकार वाली कक्षा के साथ। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वाकई न्यू नॉर्मल है, हमें निम्नलिखित प्रश्न पूछने होंगे :

- इस तरह के अभ्यास के अधिगम प्रतिफल क्या हैं? इससे विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा होता है?
- क्या इसे उपयोग करने के अवसर सबके लिए समान हैं? क्या सीखने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को यह उपलब्ध है?
- क्या *न्यू नॉर्मल* अधिगम के लिए अच्छा अनुभव है? क्या यह शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है? क्या इसे वास्तव में एक सामान्य शैक्षिक प्रयास माना जा सकता है?

आइए, हम संक्षेप में पिछले कुछ महीनों के अनुभव एवं स्कूली शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर हुए शोध के आधार पर *न्यू नॉर्मल* के बारे में पड़ताल करें।

प्रौद्योगिकी और अधिगम के प्रतिफल

शिक्षा देने के लिए *न्यू नॉर्मल* पूरी तरह से प्रौद्योगिकी-आधारित मंचों पर निर्भर है और स्कूलों ने इसे भविष्य के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। कुछ सुने-सुनाए प्रसंगों से पता चला है कि स्कूल के प्रमुख यहाँ तक कह रहे हैं कि,'इस महामारी को धन्यवाद कि हम इन तरीकों को अपना रहे हैं, अन्यथा यह स्थिति एक दशक बाद आई होती!'

सच किसी से छिपा नहीं है। कोई समाज कितना भी समृद्ध और विकसित क्यों न हो, इस महामारी से पहले उसने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं किया था, जो इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में एक परिपक्व शिक्षा प्रणाली क्या सोचती है।

यह विचार गम्भीर शोध द्वारा भी समर्थित है। अध्ययनों से पता चला है कि विद्यार्थियों द्वारा कंप्यूटर का उपयोग उनके अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। सच पूछा जाए तो उनके प्राप्तांकों में हुई गिरावट इस बात का सबूत है। इस मुद्दे की गहराई में गए बिना ही हमें इस विश्लेषण से यह तो पता चलता है कि प्रौद्योगिकी पर आधारित अधिगम के तरीक़े ऐसे समाधान नहीं हैं जिनके समर्थन के लिए धन और प्रयास ज़ाया किए जाएँ।

एक और अन्तर्दृष्टि यह है कि प्रौद्योगिकी अपने आप में कोई रामबाण नहीं है - प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल सहायता के रूप में किया जा सकता है। उसकी प्रभाविता के लिए भी कई अन्य कारकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच अधिगम के वांछनीय परिणाम नहीं देते हैं।

प्रौद्योगिकी तक पहुँच

न्यू नार्मल न केवल मशीनों और अन्य सुविधाओं पर आधारित है जैसे कि स्थाई बिजली और इंटरनेट, बल्कि विद्यार्थियों को कई अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों को अपने लिए व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता होती है, तभी वे इस तरीक़े का पूरा लाभ उठा सकते हैं। छोटे बच्चों को अपने अभिभावक की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। ये बातें आसान लग सकती हैं, लेकिन समाज के केवल कुछ ही बच्चे इनके खर्चे उठा सकते हैं, विशेष रूप से हमारे जैसे समाजों में। इसलिए क्या यह शिक्षा उतनी ही *समतामूलक* है, जितनी कि विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली कोई भी शिक्षा होनी चाहिए? यह तय करने के लिए, उपलब्ध आँकड़ों को देखना महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस) के सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रौद्योगिकी की पैठ इतनी कम है कि ऑनलाइन विधा के ज़रिए स्कूली शिक्षा को चलाने की सोच बिल्कुल असमान तरीक़े से काम करेगी। केवल 25 प्रतिशत भारतीय घरों में इंटरनेट कनेक्शन हैं और इनमें से 5 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के केवल आठ प्रतिशत विद्यार्थियों के पास निजी डिजिटल उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन हैं। दूसरी बात, हालाँकि लगभग सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन देश के आधे से भी कम घरों में दिन भर में 12 घण्टे से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। इस असमान स्थिति को देखते हुए, प्रौद्योगिकी पर आधारित *न्यू नार्मल* सामान्य नहीं हो सकता, हाँ अगर स्कूली शिक्षा के लिए *समतामूलक* पहुँच की अवधारणा को आसानी से नज़र अन्दाज़ कर दिया जाए तो बात और है।

शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

न्यू नार्मल में एक नियमित कक्षा का व्यवस्थापन हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत से शैक्षिक पहलू गायब हैं। तर्क यह दिया जा सकता है कि हमारे देश में सामान्य समय में भी कई कक्षाएँ इसी तरह संचालित की जाती रही हैं। मैं इस तर्क से सहमत हूँ, लेकिन क्या यह *न्यू नार्मल* शिक्षा का आदर्श रूप होना चाहिए? यह सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है और इसे एक सामान्य शैक्षिक प्रयास मानने के लिए इस पर गम्भीरता के साथ सोच-विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे (जिसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निकलकर सामने आई है) में कहा गया है कि शिक्षा का परिणाम 'मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास' होना चाहिए तथा वह उसमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना है जो 'हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवन्त ज्ञान समाज में लगातार बदलने में सीधे योगदान दे।' यह 1996 में यूनेस्को के इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी (जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी सन्दर्भित करता है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि पूरे जीवन की शिक्षा चार स्तम्भों पर आधारित है :

- *जानने के लिए सीखना*, यानी ज्ञान प्राप्त करना और यह सीखना कि सीखते कैसे हैं।
- *करना सीखना*, यानी कई प्रकार के कौशल प्राप्त करना जो व्यक्ति को कामकाजी जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
- *एक साथ रहना सीखना*, यानी अनेकतावाद, आपसी समझ और शान्ति के लिए सम्मान की भावना विकसित करना।
- *होने के लिए सीखना*, यानी व्यक्तित्व को विकसित करना और स्वायत्तता, निर्णय और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना।

इन सबके साथ यह भी सुनिश्चित करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता के किसी भी पहलू, स्मृति, तर्क, सौन्दर्य बोध, शारीरिक क्षमता और सम्प्रेषण कौशल की उपेक्षा न करे।

न्यू नार्मल का बेहतरीन कार्यान्वयन भी उस तरह की शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होगा जो डेलर्स समिति द्वारा सुझाए गए सीखने के चार स्तम्भों को समाहित कर पाए, जिसे 21वीं सदी के सीखने की आधारशिला के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। स्कूल स्तर पर अच्छी शिक्षा से यह अपेक्षित है कि वह ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा करे, जो मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और सौन्दर्य विकास को सम्बोधित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा शिक्षा के व्यापक और स्पष्ट नज़रिए को बताता है जिसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शामिल है, विशेष तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता का विकास - उसकी सम्पूर्ण समृद्धि और जटिलता के साथ, हाल के वर्षों में तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। इसमें आगे कहा गया है कि विद्यार्थियों को न केवल संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना होगा, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी करना होगा। जिसमें सांस्कृतिक जागरूकता और समानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क और नेतृत्व शामिल हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्य बात यह है कि मनुष्य की शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हों, वह भी एक ऐसे वातावरण में जहाँ सभी इन्द्रियबोध सक्रिय और इष्टतम हों।

सरलीकृत समाधान

महामारी के दौरान, हमारे देश के अधिकांश स्कूलों और

सार्वजनिक-स्कूल प्रणाली ने शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटरनेट-आधारित मंच का उपयोग करते हुए, स्कूल के नियमित कार्यकलापों को ऑनलाइन करने के अति सरल समाधान को अपनाया है। यह किसी भी अच्छी स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी विधा है, जो सामग्री को रोचक तरीक़े से प्रस्तुत तो कर सकती है, लेकिन इन मंचों पर जुड़ाव के जो उपकरण मौजूद हैं, वे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से संलग्न करने के लिए अपर्याप्त हैं। जब ऐसा होता है, तो फिर यह शिक्षा नहीं है। और जब यह शिक्षा नहीं है, तो इसे सामान्य नहीं माना जा सकता है - बल्कि, यह एक असामान्य स्थिति है और सामान्य स्थिति में वापसी तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए सवाल यह है कि विद्यार्थियों के सीखने के बारे में क्या किया जाए?

दीर्घकालिक प्रभाव

ब्राउन, वर्जीनिया और हार्वर्ड [i] के विद्वानों के हालिया शोध से संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में विद्यार्थी महामारी से सम्बन्धित व्यवधानों के कारण अपने सीखने के अपेक्षित स्तर से पीछे हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि ऑनलाइन शिक्षा के बावजूद अधिगम का स्तर गिर रहा है। ब्राउन और वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विद्वानों [ii] द्वारा दिए गए पेपर का सुझाव है कि पठन सीखने में यह गिरावट, अपेक्षित अंकों की एक तिहाई और गणित में यह गिरावट अपेक्षित अंकों की लगभग आधी हो सकती है। इसके अलावा एक और महत्त्वपूर्ण बात मैकिन्से [iii] अध्ययन में कही गई है कि सीखने की कमी के कारण जो नुकसान हुआ वह जीवन भर साथ रह सकता है। यह स्पष्ट है और साथ ही सिद्ध भी हो चुका है कि संयुक्त राज्य अमरीका में वंचित और हाशिए के समुदायों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जैसे ब्लैक और हिस्पैनिक विद्यार्थी। भारत में भी वंचित विद्यार्थियों पर ऐसा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है।

हमारे देश के लिए यह सब गम्भीर नुक़सान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिगम का निम्न स्तर यूँ भी एक समस्या है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि हमारे स्कूलों के लगभग 30 करोड़ विद्यार्थियों के लिए इसका क्या मतलब है। इनमें से कई विद्यार्थी दिन में एक बार मिलने वाले मध्याह्न भोजन से भी हाथ धो बैठे हैं जो उन्हें स्कूल में मिलता था।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि संरचित अधिगम आवश्यक है। बच्चों को केवल जीवित रहते हुए सीखने देना, या अपने अब तक के जीवन के अनुभवों से सीखने देना किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में जिन बच्चों को सीखने के संरचित माहौल में शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनके अधिगम में जो कमियाँ रह जाएँगी, उसका प्रभाव बड़े होने पर उनकी आजीविका के अवसरों पर पड़ेगा। यह ज़रूरी है कि अधिगम के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाएँ। इस सन्दर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि गैर-प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित किए जाएँ ताकि जिन विद्यार्थियों की पहुँच तकनीकी संसाधनों तक नहीं है, उन्हें भी सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

यदि एक ओर वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है तो दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन मंच पर हैं, उन्हें सन्तुलित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होंगे, जिसमें न केवल उसके सीखने की ज़रूरतें, बल्कि उसके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक-भावनात्मक भलाई भी शामिल हो। भले ही प्रौद्योगिकी-आधारित विधा का उपयोग किया जाए, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इन बातों पर विचार किया जाए : प्रतिदिन स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय की अधिकतम अवधि, विद्यार्थी द्वारा तकनीकी उपकरण के उपयोग की बारम्बारता, अन्तःक्रियात्मक सत्र के लिए विभिन्न मंचों की उपयुक्तता, अभिभावकों द्वारा निगरानी की आवश्यकता, विभिन्न आयु समूहों के लिए अलग-अलग मापदण्ड, समकालिक विधा में क्या और असमकालिक विधा में क्या हो सकता है, क्या वह सक्रिय अधिगम हो या निष्क्रिय आदि।

व्यावहारिक समाधान

> दुनिया भर के सर्वोत्तम अभ्यासों का सुझाव है कि जब तक नियमित स्कूल शुरू न हों, तब तक विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए और उस मिश्रित तरीक़े को काम में लाना चाहिए। अधिगम की मिश्रित रणनीतियों में समकालिक (या लाइव) और असमकालिक (या रिकॉर्ड की गई) प्रौद्योगिकी-आधारित अधिगम का मिश्रण और साथ में विद्यार्थियों का अपने समुदाय के सहपाठियों के साथ छोटे-छोटे समूहों में आमने-सामने की चर्चाएँ करना भी शामिल है। ये रणनीतियाँ आवश्यक हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी के प्रश्न से परे शैक्षिक प्रक्रियाओं का प्रश्न है। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षा, जहाँ तक सम्भव हो, वांछित स्तर के काफ़ी क़रीब हो। नियमित पाठ्यक्रम या इसका केवल एक छोटा हिस्सा इस समय की माँग नहीं है। विद्यार्थियों की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, और स्कूलों को उनका जवाब शैक्षिक रूप से सार्थक तरीक़े से देना चाहिए न कि किसी सरल तरीक़े से जैसा कि आजकल अधिकतर स्कूलों में दिखाई दे रहा है।

चूँकि प्रत्येक बच्चे के पास डिजिटल संसाधन नहीं होते हैं, अतः कई विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। ताकि शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को वंचित न किया जाए और हमारे पहले से

ही नाज़ुक और असमान समाज में और दूरियाँ न पैदा हों। कई दिशानिर्देश विकसित हुए हैं। हमारे देश की केन्द्रीय अकादमिक संस्था, एनसीईआरटी ने प्रज्ञता (PRAGYATA) नामक दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसमें आठ विशिष्ट चरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सीखना जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता है।

इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समय विद्यार्थियों पर विषय-सामग्री का बोझ डालने की बजाय कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए सीखने को सीखना - यह कौशल इस समय काफ़ी महत्त्व का है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सीखना जारी रखने के लिए आत्म-अधिगम एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इसी सन्दर्भ में हमें आकलन के बारे में भी फिर से कल्पना करनी होगी।

विद्यागमा

कर्नाटक शिक्षा विभाग ने वैज्ञानिक रूप से विकसित अधिगम के एक मिश्रित कार्यक्रम का निर्माण किया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास महामारी के दौरान भी अधिगम का औपचारिक माहौल हो। यह एक उत्कृष्ट अभ्यास है और इस प्रयोग से मिली सीख के आधार पर इसे देश भर में लागू किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम का निर्माण समग्र शिक्षण कर्नाटक (एसएसके) तथा राज्य शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण विभाग (डीएसईआरटी) कर्नाटक द्वारा किया गया था और इसमें सीखने के लिए कई चैनल शामिल हैं, जैसे यू-ट्यूब चैनल - जिनका उपयोग स्मार्टफ़ोन की मदद से किया जा सकता है। जहाँ इंटरनेट की सुविधा न हो वहाँ टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आमने-सामने शिक्षण के लिए सामुदायिक स्कूल या वटारा शाले का आयोजन भी किया गया।

कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह हैं :

- *मक्कलवाणी* यू-ट्यूब चैनल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जनसामान्य से प्राप्त सामग्री (पाठ-से-गतिविधियाँ) के आधार पर शिक्षकों ने बनाया। यह 50 दिनों तक चला। वीडियो देखने वालों की संख्या 7000 से 1,36,000 तक थी। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए डीडी चन्दना और आकाशवाणी के माध्यम से मक्कलवाणी के चुनिन्दा कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।
- *सम्वेदा* यू-ट्यूब चैनल विशेष रूप से हाई स्कूल स्तर के विषयों के शिक्षण के लिए एक ब्रिज कोर्स के रूप में था।
- *वटारा शाले* में शिक्षक अपने-अपने गाँव के सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों के साथ जुड़ते हैं। उनकी भूमिका एक वयस्क सुगमकर्ता की होती है। विद्यार्थी उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। इस बारे में दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ बनाई गईं कि सम्पर्क कैसे होना चाहिए और सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियाँ कैसे रखी जानी चाहिए। एक मुहल्ले के बीस से पच्चीस विद्यार्थियों को एक साथ रखा गया और उनके साथ एक शिक्षक होते थे। कार्यक्रम की प्रमुख बात यह थी कि सीखने की कमियों को कम किया जाए। शिक्षकों से यह अपेक्षा थी कि वे विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए इस अवधि के दौरान चार निर्माणात्मक आकलन करें।

दुर्भाग्य से इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया क्योंकि कुछ गाँवों में कोविड-पॉज़िटिव मामले रिपोर्ट किए गए थे। यह सीख उसी बात को दोहराती है जो हमने पिछले कुछ महीनों में सीखा यानी जिस स्थिति का सामना हम कर रहे हैं, उसका कोई एक जैसा समाधान नहीं हो सकता। पूर्ण लॉकडाउन जैसे चरम उपाय न तो अर्थव्यवस्था के पक्ष में काम करते हैं और न ही शिक्षा के।

आगे की राह

आगे का रास्ता यह है कि एक सन्तुलित दृष्टिकोण रखा जाए। जहाँ तक स्कूलों का सम्बन्ध है, इस बात का निर्णय समुदाय पर छोड़ना बेहतर होगा कि विद्यार्थियों का अधिगम कैसे सुनिश्चित किया जाए। स्कूल प्रबन्धन समितियाँ समुदाय के लिए निर्णय लेने के लिए सबसे उचित हैं। चूँकि अभिभावक और शिक्षण स्टाफ इन समितियों के सदस्य होते हैं, अतः वे निर्णय ले सकते हैं कि स्कूल खोले जाएँ या नहीं। अगर खोले जाएँ तो प्रत्येक कक्षा के लिए किस अन्तराल पर खोले जाएँ। यदि किसी कोविड-19 पॉज़िटिव केस की पहचान हो जाए तो स्कूल बन्द करने का निर्णय लेना भी आसान है। अन्य दिशा-निर्देश, जैसे कि दी जाने वाली विषय-सामग्री और सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि आदि को राज्य स्तर पर विकसित करके साझा किया जा सकता है।

यह एक असामान्य स्थिति है जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं और हमें इसका उपयोग प्रभावी तथा अच्छे तरीक़े से करना होगा। वैसे कठिन परिस्थिति से कुछ अच्छा प्राप्त करना निश्चित रूप से न्यू नार्मल नहीं है। स्कूली शिक्षा के बारे में हम जिस सामान्य स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह यह है कि विद्यार्थी और शिक्षक एक-दूसरे के साथ जीवन्त कक्षाओं, कक्षा के बाहर की गतिविधियों और चर्चाओं में शामिल हों। यह सभी तरीक़े ही वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सबसे उपयुक्त तरीक़े हैं।

References

Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development. 2020. *PRAGYATA – Guidelines for Digital Education*

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf

National Council of Educational Research and Training. (2020). *Alternative Academic Calendar for Students—Secondary*. https://seshagun.gov.in/sites/default/files/update/Academic%20Calender%20-%20Secondary%20-%20Eng.pdf

What Is So Wrong with Online Teaching? (2015). *Economic and Political Weekly*, 55(23), 7–8.

World Bank. (2020). *Guidance Note: Remote Learning & COVID-19*. http://documents1.worldbank.org/curated/en/531681585957264427/pdf/Guidance-Note-on-Remote-Learning-and-COVID-19.pdf

Ministry of Human Resource Development (MHRD). 2019. *The Draft National Education Policy, 2019*

Department of Primary and Secondary Education, Government of Karnataka. 2020. *Circular on implementing Vidyagama program* http://www.schooleducation.kar.nic.in/pdffiles/VidyagamaCircular04082020.pdf

Delors, Jacques et al. 1996. *Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*.

"The Economic Tracker", accessed July 2, 2020, https://tracktherecovery.org/.

Megan Kuhfeld et al., "Projecting the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Academic Achievement," *EdWorkingPapers.Com* (Annenberg Institute at Brown University, 2020), https://www.edworkingpapers.com/ai20-226.

"Achievement Gap and Coronavirus | McKinsey," accessed July 2, 2020, https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime

[i] https://tracktherecovery.org/ Central Square Foundation. July 2020. State of the Sector Report – Private Schools in India. New Delhi.

[ii] https://www.edworkingpapers.com/ai20-226

[iii] https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime

बी. एस. ऋषिकेश अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफ़ेसर और हब फ़ॉर एजुकेशन, लॉ और पॉलिसी के लीडर हैं। शोध और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें 20 वर्ष का अनुभव है। वे पिछले 15 वर्षों से अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन में कार्यरत हैं। वे कर्नाटक सरकार के साथ नीतिगत मामलों पर कार्य करते हैं और शिक्षा विभाग द्वारा गठित कई समितियों के सदस्य हैं। उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा मॉडल का अध्ययन करने वाली समिति के लिए नामित किया गया था। वे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में शैक्षिक नीति से सम्बन्धित मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। उनसे **rishikesh@apu.edu.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल

अब समय आ गया है कि हम यह तय करें कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें ऑनलाइन, दिमाग़ी और अन्यायपूर्ण शिक्षा प्रक्रियाओं की तरफ़ और अधिक बढ़ना चाहिए? या फिर हमें विपरीत दिशा की ओर बढ़ना चाहिए यानी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर, जिसमें अधिक निकटता और सम्पर्क है? यदि हम दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो हमें छोटे-से-छोटे गाँवों में भी बच्चों को एक साथ लाने के तरीक़ों में निवेश करना होगा (मास्क, हाथ धोने और शारीरिक दूरी की सभी सावधानियों के साथ)। इन तरीक़ों के ज़रिए बच्चे एक-दूसरे के साथ हो सकते हैं और शिक्षक के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ शिक्षक से तात्पर्य एक ऐसे वयस्क से है जो वार्तालाप और सीखने का सुगमीकरण कर सके और किताबों, पेंसिल और काग़ज़ के साथ काम कर सके

- हृदय कान्त दीवान, 'शिक्षा : हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?', पेज 7